तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023

संदर्भ: तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया गया है

मुख्य विशेषताएं:

- **छोटे किसानों को सशक्त बनाना:** तटीय जलीय कृषि को सीआरजेड-अनुमत के रूप में पुनः पुष्टि की गई; यह बहु-एजेंसी मंजूरी को आसान बनाता है
- **छूट और स्पष्टता:** सीआरजेड के नो डेवलपमेंट जोन (एनडीजेड) में हैचरी की अनुमति; यह अनुपालन न करने पर जुर्माना कठोर दंड को नागरिक दंड से बदल देता है।
- **पर्यावरण-अनुकूल प्रथाएं**: पर्यावरण-अनुकूल जलीय कृषि (पिंजरे की संस्कृति, समुद्री शैवाल, आदि) को प्रोत्साहित करती है; रोग-मुक्त स्टॉक; एंटीबायोटिक्स पर सीमित ध्यान देता है।
- **व्यवसाय में आसानी:** परिचालन प्रक्रियाओं को सरल बनाता है; परिवर्तनों के लिए पंजीकरण समायोजित करता है; प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाता है.
- **पर्यावरण अनुपालन**: उत्सर्जन मानक निर्धारित करता है; "प्रदूषक भुगतान सिद्धांत" लागू करता है; संवेदनशील क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है
- **विकास और उपलब्धियां**: 9 वर्षों में झींगा उत्पादन तीन गुना (3.22L टन से 11.84L टन); समुद्री खाद्य निर्यात दोगुना(30,213 करोड़ रुपये से 63,969 करोड़ रुपये); झींगा निर्यात में 123% की वृद्धि (19,368 करोड़ रुपये से 43,135 करोड़ रुपये) हुई।
- **अस्पष्टताओं को संबोधित करना**: सीआरजेड-अधिसूचना विवादों को हल करना; प्रगतिशील, स्पष्ट कानून को बढ़ावा देता है।
- **सतत दृष्टि:** विधेयक सर्वोत्तम प्रथाओं, विविधीकरण और सुरक्षित उत्पादों का परिचय देता है; आय और रोजगार बढ़ाता है।
- **आर्थिक प्रभाव:** छोटे किसानों को समर्थन; ईंधन निर्यात; जलकृषि-आधारित नौकरियों और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है।

तटीय विनियमन क्षेत्र

- **सीआरजेड-I (पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र):** विशिष्ट परियोजनाओं जैसे कि परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए सीमित निर्माण की अनुमति ; मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियों और जीवमंडल जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में कोई नया निर्माण नहीं
- **सीआरजेड-II (नगरपालिका सीमा के भीतर विकसित क्षेत्र):** खतरनाक रेखा से भूमि की ओर इमारतों की अनुमति; अन्य अलवणीकरण संयंत्र जैसी गतिविधियों की अनुमति; निर्माण के लिए दिशानिर्देशों का पालन करता है।
- **सीआरजेड-III (अबाधित और ग्रामीण क्षेत्र):** नो डेवलपमेंट जोन (0-200 मीटर से) के भीतर किसी भी विकास की अनुमति नहीं है; प्रतिबंधित क्षेत्र (200-500 मीटर)मे स्थानीय सामुदायिक आवास, कुछ परियोजनाओं आदि जैसी गतिविधियों की अनुमति देता है पारंपरिक गतिविधियाँ; इसका उद्देश्य अपेक्षाकृत अबाधित क्षेत्रों को संरक्षित करना है।
- **सीआरजेड-IV (निम्न ज्वार रेखा से प्रादेशिक सीमा तक जलीय क्षेत्र**): स्थानीय समुदायों द्वारा पारंपरिक मछली पकड़ना अनुमति है; जलीय क्षेत्र में अनुपचारित सीवेज या ठोस अपशिष्ट निपटान पर सख्त प्रतिबंध।
- **द्वीप संरक्षण क्षेत्र अधिसूचना: अद्वितीय** की सुरक्षा के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी किया गया ,अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों के पारिस्थितिकी तंत्र को संभावित खतरों से बचाना।

भारत की सौर ऊर्जा क्षमता

संदर्भ: संसद में एक उत्तर के अनुसार, भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 70.1 गीगावॉट है।

- **सौर क्षमता का आकलन:** राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ने सौर पीवी मॉड्यूल के साथ 3% बंजर भूमि कवरेज पर विचार करते हुए भारत की सौर क्षमता 748 गीगावॉट का अनुमान लगाया है।
- **महत्वाकांक्षी नवीकरणीय लक्ष्य**: भारत का लक्ष्य 2022 तक 175 गीगावॉट और 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय क्षमता का लक्ष्य है, जो नवीकरणीय ऊर्जा में दुनिया की सबसे बड़ी विस्तार योजना है।
- **सौर पीवी नेतृत्व:** भारत नई सौर पीवी क्षमता (2021 में 13 गीगावॉट जोड़ा गया) के मामले में एशिया में दूसरे और विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है; जबकि कुल स्थापनाओं पहली बार जर्मनी (59.2 गीगावॉट) को पीछे छोड़ते हुए 60.4 गीगावॉट के साथ चौथे स्थान पर है।
- **भारत में अग्रणी सौर ऊर्जा उत्पादक:** राजस्थान (17839.98 मेगावाट), गुजरात (10133.66 मेगावाट), आंध्र प्रदेश (4552.12 मेगावाट), तमिलनाडु (6892.81 मेगावाट), कर्नाटक (9050.59 मेगावाट)।

परिचालन योजनाएं

- सौर पार्क योजना का लक्ष्य, कम से कम 50 सौर पार्कों में 40,000 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य है।
- व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) के साथ 12,000 मेगावाट ग्रिड-कनेक्टेड सौर पीवी पावर परियोजनाओं के लिए योजना।
- ग्रिड-कनेक्टेड सोलर रूफटॉप पावर प्लांट की स्थापना।
- विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों, स्टैंड-अलोन सौर पंपों और कृषि पंपों के सौरीकरण के लिए प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)।
- "उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम" के तहत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।
- अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली विकास के लिए हरित ऊर्जा गलियारा योजना।

वित्तीय सहायता:

- **सोलर पार्क योजना:** डीपीआर तैयार करने के लिए प्रति सोलर पार्क 25 लाख रुपये तक और पार्क के बुनियादी ढांचे के लिए 20 लाख रुपये प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 30%।
- **सीपीएसयू योजना चरण- II**: बोली के माध्यम से चयनित सीपीएसयू/सरकारी संगठनों को प्रति मेगावाट 55 लाख रुपये तक व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) सहायता।
- **ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट:** 3 किलोवाट तक की आवासीय क्षमता के लिए 40% तक केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए), और डिस्कॉम के लिए 10% तक प्रोत्साहन।
- **पीएम-कुसुम योजना**: डिस्कॉम के लिए खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई), स्टैंड-अलोन सौर पंपों के लिए सीएफए और कृषि पंपों का सौर्यीकरण।
- **उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना**: बिक्री, प्रदर्शन मापदंडों और स्थानीय मूल्यवर्धन के आधार पर उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन।
- **हरित ऊर्जा गलियारा योजना:** डीपीआर या आवंटित लागत के चरण-I में 40% और चरण-II में 33% का सीएफए।

इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क

संदर्भ: इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क ने अपने नए सदस्य के रूप में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अकादमी का स्वागत किया है।

अवलोकन

- यह नेटवर्क दुनिया भर में कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
- सीबीआई अकादमी इस नेटवर्क से जुड़ने वाला 10वां सदस्य है.
- यह सहयोग विश्व स्तर पर पुलिस कर्मियों को उच्च गुणवत्ता वाले क्षमता निर्माण, क्षमता विकास और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है।
- इस साझेदारी से दुनिया भर के कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ-साथ भारतीय पुलिस कर्मियों को भी लाभ होगा।

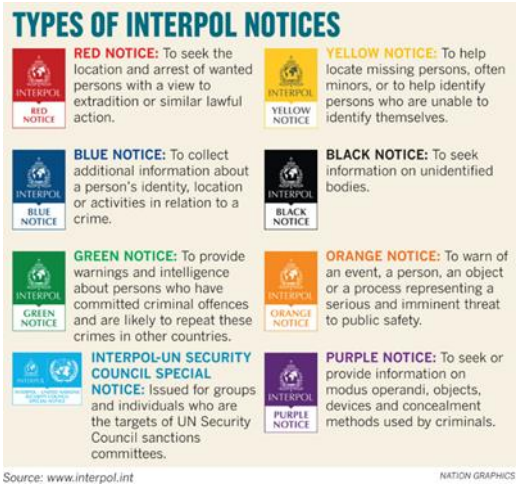

इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क

- कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण के लिए इंटरपोल के वैश्विक दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क 2019 में शुरू हुआ।
- यह कानून प्रवर्तन कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए विश्वव्यापी पद्धति को बढ़ावा देने के इंटरपोल के मिशन का समर्थन करता है।
- नेटवर्क में विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य दुनिया भर में कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण संस्थानों के बीच विद्वानों के सहयोग को बढ़ावा देना है।

इंटरपोल

- इंटरपोल 195 सदस्य देशों वाला एक अंतरसरकारी संगठन है।
- इसका मुख्य लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को सुविधाजनक बनाना है।
- इंटरपोल का मुख्यालय ल्योन, फ्रांस में स्थित है।
- यह प्रत्येक सदस्य देश में राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) के माध्यम से संपर्क बिंदुओं के रूप में कार्य करता है।
- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इंटरपोल नेटवर्क के भीतर भारत के नामित एनसीबी के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 2.0

संदर्भ: DOPPW ने नवंबर 2023 में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 2.0 के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे 70 लाख केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को लाभ होगा।

दिशानिर्देश क्या हैं?

- पेंशन जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए पेंशनभोगियों को हर साल नवंबर (80 वर्ष और उससे अधिक उम्र वालों के लिए अक्टूबर) में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) सुविधा के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (DLC) प्रदान करता है। इसकी शुरुआत बायोमेट्रिक सबमिशन से हुई और बाद में स्मार्टफोन-आधारित सबमिशन के लिए आधार डेटाबेस का उपयोग करके फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक पेश की गई।
- नवंबर 2022 में 37 शहरों में एक सफल राष्ट्रव्यापी अभियान चला, जिसमें 35 लाख से अधिक डीएलसी जारी किए गए।
- नवंबर 2023 में 100 शहरों में 50 लाख पेंशनभोगियों को लक्षित करते हुए एक और अभियान की योजना बनाई गई है तथा सभी हितधारकों के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए।
- दिशानिर्देशों में नोडल अधिकारी, बैनर/पोस्टर के माध्यम से जागरूकता, डोरस्टेप बैंकिंग उपयोग, एंड्रॉइड से लैस बैंक कर्मचारी, शिविर और घर का दौरा शामिल है।
- पेंशनभोगी कल्याण संघों को डीएलसी शिविर आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, DoPPW टीमें पेंशनभोगियों की सहायता करेंगी और जागरूकता के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग किया जाएगा।

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (जीवन प्रमाण)

- 10 नवंबर 2014 को लॉन्च किया गया, जीवन प्रमाण पेंशनभोगियों के लिए बायोमेट्रिक-संचालित डिजिटल समाधान प्रदान करता है।
- यह सेवा केंद्र, राज्य और अन्य सरकारी निकायों के सेवानिवृत्त लोगों के लिए खुली है, जिसमें तीन करोड़ से अधिक पूर्व सरकारी और पीएसयू कर्मचारी शामिल हैं।
- सेवानिवृत्ति के बाद, पेंशनभोगियों को पेंशन प्राप्त करने के लिए बैंक या डाकघर जैसी अधिकृत एजेंसियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- परंपरागत रूप से, इसमें व्यक्तिगत उपस्थिति या पूर्व नियोक्ता से प्राप्त प्रमाणपत्र शामिल होता है।
- जीवन प्रमाण पेंशन जारी रखने के लिए साक्ष्य को डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है, जिससे भौतिक उपस्थिति या नियोक्ता प्रमाणपत्र की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- हालाँकि, पुनर्विवाहित या पुन: नियोजित पेंशनभोगियों को अभी भी अपने पेंशन संवितरण प्राधिकरण को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पारंपरिक प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- **कार्यरत:**
  - जीवन प्रमाण पेंशनभोगियों के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करता है।
  - जब प्रमाणीकरण सफल हो जाता है, तो एक डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तैयार किया जाता है और जीवन प्रमाणपत्र भंडार में संग्रहीत किया जाता है।
  - पेंशन वितरण एजेंसियां आसानी से ऑनलाइन प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकती हैं।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

10 August, 2023

NEWS IN BETWEEN THE LINES

डीकार्बोनाइजेशन

डीकार्बोनाइजेशन क्या है?

डीकार्बोनाइजेशन का अर्थ है पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना या हटाना, सामान्यता ऊर्जा स्रोतों और अधिक पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाकर ऐसा किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र लक्ष्य 7: सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ ऊर्जा सुनिश्चित करना।

जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता: 82% ऊर्जा जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करना।

डीकार्बोनाइजेशन की चुनौतियाँ:

- **सौर/पवन अपर्याप्त:** वर्तमान में यह किफायती ऊर्जा नहीं।
- **महत्वपूर्ण खनिजों की मांग:** स्वच्छ-ऊर्जा खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है।
- **भू-राजनीतिक/पर्यावरण:** खनन चुनौतियाँ।

परमाणु ऊर्जा की भूमिका:

- **10% वैश्विक बिजली**: परमाणु, गैस, CO_2 उत्सर्जन में कटौती करता है।
- **विश्वसनीय ग्रिड**: निरंतर बिजली, कम एकीकरण लागत प्रदान करता है।

छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर):

- **कॉम्पैक्ट, सुरक्षित:** कम कोर क्षति, विकिरण जोखिम।
- **साइटों का पुन:उपयोग करें:** मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करें, भूमि बचाएं।
- **लागत कुशल**: फ़ैक्टरी-निर्मित, कम जोखिम।

भविष्य का अनुमान: किफायती, लगभग 60-90 डॉलर प्रति मेगावाट।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

पृष्ठभूमि:

PMJAY: केंद्र की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है।

मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

लॉन्च तिथि: फरवरी 2018

कवरेज: माध्यमिक देखभाल (गैर-सुपर विशेषज्ञ) और तृतीयक देखभाल (सुपर विशेषज्ञ) चिकित्सा सेवाओं दोनों के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये का कवरेज।

ऑडिट अनावरण और सत्यापन मुद्दे:

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा उजागर किए गए इस योजना में अनियमितताओं का खुलासा हुआ है और लाभार्थी सत्यापन प्रक्रियाओं के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।

सत्यापन प्रक्रिया:

- मंत्रालय ने कहा कि मोबाइल नंबरों का उपयोग लाभार्थियों के सत्यापन के लिए नहीं किया जाता है।
- आधार-आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से लाभार्थी की पहचान की जाती है।

सीएजी निष्कर्ष:

मामले: मृत मरीजों का इलाज, एक ही आधार या अमान्य मोबाइल नंबर का उपयोग करने वाले कई लोग।

उदाहरण: 7.5 लाख लाभार्थी एक ही सेलफोन नंबर (9999999999) से जुड़े हुए हैं।

तमिलनाडु: केवल सात आधार नंबरों के साथ 4,761 पंजीकरण।

अमेज़न सहयोग संधि संगठन क्या है?

अमेज़न सहयोग संधि संगठन (एसीटीओ) अमेज़न बेसिन देशों के बीच सतत विकास को बढ़ावा देने और अमेज़न वर्षावन की सुरक्षा के लिए एक प्रयास है।

एसीटीओ स्थापना:

- **ACT के माध्यम से फाउंडेशन**: अमेज़न सहयोग संधि (ACT) पर 3 जुलाई, 1978 को हस्ताक्षर किए गए और 1998 में संशोधित किया गया, जिससे सहयोग का आधार बना।
- **ACTO की शुरुआत:** संधि के उद्देश्यों के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए 1995 में ACTO का उद्घाटन किया गया था।
- **स्थायी सचिवालय:** अपनी संगठनात्मक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए, 2002 में ब्रासीलिया में एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की गई थी।

सदस्य देश:

- बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेज़ुएला।
- अमेज़न से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए बेलेम, ब्राज़ील में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए।

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं:

- ब्राज़ील में आयोजित, अमेज़न वर्षावन को बचाने पर केंद्रित।
- वर्षावनों को "वापसी न करने योग्य बिंदु" तक पहुँचने से रोकना है।

नई औषधि एवं नैदानिक परीक्षण नियम (2023)

नियमों में संशोधन:

भारत सरकार द्वारा संशोधित, नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम (2023) का उद्देश्य अनुसंधान में, विशेष रूप से दवा परीक्षण में जानवरों के उपयोग को कम करना है।

उद्देश्य:

नियमों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अनुसंधान में, विशेषकर दवा विकास प्रक्रियाओं में पशु परीक्षण पर निर्भरता को कम करना है।

मानव प्रतिक्रिया के लिए सीमित पूर्वानुमान:

जैविक भिन्नताओं के कारण दवाओं के प्रति जानवरों की प्रतिक्रियाएँ मनुष्यों से भिन्न हो सकती हैं।

उदाहरण: थैलिडोमाइड ने पशु परीक्षणों में उत्तीर्ण होने के बावजूद मानव जन्म दोषों का कारण बना।

अन्य देशों द्वारा किए गये प्रयास:

- **यूरोपीय संघ (2021):** अनुसंधान, नियामक परीक्षण और शिक्षा में गैर-पशु विकल्पों के लिए संकल्प लिया गया।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका (2022):** एफडीए आधुनिकीकरण अधिनियम 2.0 दवा परीक्षण के लिए गैर-पशु प्रणालियों की अनुमति देता है।
- **दक्षिण कोरिया (2022):** 'पशु परीक्षण विधियों के विकास, प्रसार और विकल्पों के उपयोग को जीवंत बनाना' विधेयक पेश किया गया।
- **कनाडा (जून 2023)**: विषाक्तता परीक्षण में कशेरुक जानवरों के उपयोग को कम करने के लिए संशोधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पेश किया गया।

ऑकस

ऑकस क्या है?

AUKUS का मतलब "ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप" है। यह ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गठित एक त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन है।

गठन: ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी।

फोकस: विशेष रूप से भारत-प्रशांत क्षेत्र में रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना।

पनडुब्बी सौदा: ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन की तकनीक वाली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हासिल करेगा।

रणनीतिक लक्ष्य: क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, खतरों को रोकना, इंडो-पैसिफिक में स्थिरता को बढ़ावा देना।

कूटनीतिक तनाव: फ्रांस के पनडुब्बी सौदे को रद्द करने से तनाव पैदा हो गया।

वैश्विक गठबंधन: यह विकसित हो रहे वैश्विक गठबंधनों और साझेदारियों को दर्शाता है।

धारणाएं अलग-अलग हैं: विभिन्न हितधारक AUKUS को अलग-अलग तरह से देखते हैं, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और बहुपक्षीय सहयोग पर असर पड़ता है।

विश्व जैव ईंधन दिवस

तिथि: विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है।

सर रुडोल्फ डीजल की स्मृति में: यह दिन डीजल इंजन के आविष्कारक सर रुडोल्फ डीजल के योगदान को याद करता है।

जैव ईंधन का महत्व: यह आयोजन ऊर्जा परिदृश्य में जैव ईंधन के वैश्विक महत्व को रेखांकित करता है।

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति:

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसे 2018 में लॉन्च किया था।
- जून 2022 में और संशोधन हुए।

उद्देश्य: घरेलू जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देकर पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना।

यूएफआई (यूनिवर्सल फोर्सेज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड):

भूमिका: बांस आधारित इथेनॉल उत्पादन के लिए प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण में सहयोगी।

स्थापना: 1996 में स्थापित।

विशेषज्ञता: 27 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ आधुनिक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी में अग्रणी।

ग्राहक: वैश्विक स्तर पर 150 से अधिक संरक्षकों को सेवा प्रदान करता है।

प्रमाणपत्र: आईएसओ 9001:2015, आईबीआर, एएसएमई।

समाचारों में स्थान

कीलाडी

स्थान: कीलाडी तमिलनाडु में मदुरै से 12 किमी दक्षिण पूर्व में स्थित है।

राजनीतिक सीमाएँ: एक भारतीय राज्य तमिलनाडु की राजनीतिक सीमाओं के भीतर स्थित है।

भौतिक विशेषताएं: कोयंबटूर क्षेत्र के निकट स्थित, क्रिस्टल क्वार्ट्ज सहित अपने भूवैज्ञानिक संसाधनों के लिए जाना जाता है।

हालिया खोज: पुरातत्वविदों ने कीलाडी में संगम युग की एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन इकाई का पता लगाया।

अद्वितीय डिजाइन: क्रिस्टल इकाई का आकार गोलाकार है, जिसका व्यास 2 सेमी और ऊंचाई 1.5 सेमी है, वजन 8 ग्राम है।

अतिरिक्त खोज: उत्खनन से एक टेराकोटा होपस्कॉच, एक लोहे की कील, काले और लाल बर्तन, लाल फिसलन वाले बर्तन और एक मिट्टी के साँप की मूर्ति भी मिली।

ऐतिहासिक महत्व: इतिहासकार और पुरातत्वविद् इस खोज से आश्चर्यचकित हैं क्योंकि अतीत की अधिकांश वजन इकाइयाँ पत्थरों से बनी थीं।

वर्तमान उत्खनन: कीलाडी वर्तमान में उत्खनन के नौवें चरण से गुजर रहा है, जिसकी शुरुआत अप्रैल में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने की थी।

संगम युग का विस्तार: तमिलनाडु में चल रही खुदाई ने संगम युग की समयसीमा को 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक बढ़ा दिया है।

POINTS TO PONDER

- **किस प्रकार का नेत्रश्लेष्मलाशोथ लोगों के बीच फैलता है**? -वायरल और बैक्टीरियल
- **नोवो नॉर्डिस्क की प्रभावी मोटापे की दवा का क्या नाम है**? -वेगोवी
- **लौवर महल किस नदी के तट पर स्थित है**? -सीन
- **पेरिस के अलावा, एशिया में आधिकारिक लौवर संग्रहालय कहाँ स्थित है**? -आबू धाबी
- **चंद्रयान3 की कक्षा न्यूनीकरण प्रक्रिया किसने की**? -इस्ट्रैक